>

Title: Need to take a relook on the definition of poverty line and make it realistic in consonance with the ground realities.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): गरीबी की नई परिभाषा वास्तव में देश के गरीबों की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है। 2004-05 में जहाँ गरीबों की तादाद कुल जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत थी वह घटकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गई। इन आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। देश के गांवों में अब भी लगभग 27 करोड़ लोग गरीब है और शहरों में 5 करोड़ 31 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे है यानि देश की कुल आबादी का एक-चौथाई अब भी गरीब है। योजना आयोग द्वारा गरीबों की संख्या घटाकर बताने तथा गांवों में 27 रूपये प्रतिदिन कमाने वाला एवं शहरों में 33 रूपये रोज कमाने वाला गरीबी रेखा में नहीं आता है, यह जनता के गले नहीं उतर रही है। क्या सिर्फ पेट भरना गरीबी से पार होने की परिभाषा है जिन्हें गरीबी रेखा के ऊपर माना जा रहा है क्या उन्हें साफ पानी, सफाई, बच्चों की शिक्षा, पौष्टिक आहार आदि मिल पा रहा है ? अगर नहीं मिल रहा तो कैसे मान लिया जाए कि वे गरीबी रेखा से ऊपर है ? क्या रोजगार बढ़ रहे हैं ? जब रोजगार नहीं बढ़ेगे तो गरीबी कैसे मिटेगी। जरूरत है उसे मिटाने के लिए बड़ी और सार्थक योजनाएं बनाने की ,उससे भी बढ़कर उनका कार्यान्वयन करने की।